हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 16 | देहरादून, शनिवार, 02 जुलाई, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

कोटद्वार का चहुमुखी विकास मेरा लक्ष्य : ऋतू खंडूड़ी , स्पीकर

3

एक दिन ऐसा आएगा जब सिफारिश या कतार में लगने की जरूरत नहीं रहेगी : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अधिकारियों से तीन महीने में अगले तीन साल का रोडमैप बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसी योजनाएं तैयार करें, जिन्हें नौ नवंबर 2025 तक पूरा कर जनता के सामने पेश किया जा सके। पहले तीन साल और फिर 10 साल का रोडमैप बनाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। इस अवसर पर धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के 51 लाभार्थियों को चेक और चाबी सौंपी। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में पांच हजार लोगों को आवास मिले हैं।

योजना की शुरुआत

कैंट रोड स्थित सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से सहायतित 771 करोड़ की रूरल इंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम का भी उद्घाटन किया। साथ ही कृषि-औद्यानिक दृष्टि पत्र-2027

एवं रेशम विभाग के आगामी पांच वर्षों के लिए दृष्टि पत्र का विमोचन किया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से प्रशिक्षित 50 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

चंपावत में मधुग्राम और तेज पत्ता उत्पादन : इस मौके पर सीएम ने कहा कि मधुग्राम योजना के तहत चंपावत में सिप्टी न्याय पंचायत और देहरादून में चामासारी (रायपुर) को विकसित किया जाएगा। तेज पत्ता उत्पादन के सर्वांगीण विकास के लिए चंपावत के खतेड़ा राजकीय उद्यान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर टनकपुर एवं गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास भी किया। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर सीएम ने उल्टी दौड़ में रिकार्ड बनाने वाले पूर्व सैनिक मोहन सिंह को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, खाद्य मंत्री रेखा आर्य, विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, भोपाल राम टम्टा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव सचिन कुर्वे, शैलेश बगोली, दीपेन्द्र चौधरी आदि मौजूद रहे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी कार्मिक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चलते हुए काम करें। जनता के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास का भाव आना चाहिए। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब सिफारिश या कतार में लगने की जरूरत नहीं रहेगी।

एक नज़र उद्घाटन-विमोचन-घोषणाओं पर : चंपावत का खतेड़ा उद्यान तेजपत्ता के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचंपावत का सिप्टी और दून का चामासारी गांव मधुग्राम के रूप में विकसित होंगेकृषि-उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग का पांच साल का दृष्टिपत्र जारीपीएम आवास योजना के 51 लाभार्थियों को सौंपी मकान की चाबी और चेककौशल विकास योजना से प्रशिक्षित 50 लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

कन्या श्री योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने लड़कियों को बांटी साईकिल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा आयोजित कन्याश्री कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं... कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास सभी के सहयोग से संभव है. कन्याश्री योजना के शुभारंभ पर उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान चल रहा है... उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए रोटरी क्लब व अन्य सामाजिक संगठनों की भी अहम भूमिका होगी... इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस नीति से काम कर रहे हैं.

इसके लिए 1064 नंबर लांच किया गया है, इस नंबर पर पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है... आपको यहाँ बता दें कि हर साल एक जुलाई रोटरी क्लब से नए सत्र की शुरुआत की जाती है. इस वर्ष के नए सत्र की शुरुआत आज से की गई, जिसमें रोटरी क्लब काशीपुर के नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में पवन अग्रवाल को अगले 1 वर्ष के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुना गया. रोटरी क्लब के इस वर्ष के सत्र को कन्या श्री योजना का नाम दिया गया है. कन्याश्री योजना के तहत रोटरी क्लब के द्वारा पूरे रोटरी मंडल भर में 2100 साइकिलों का निर्धन छात्राओं को निःशुल्क वितरण किया गया... काशीपुर में इस योजना के तहत 200 निर्धन छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया. रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के द्वारा आयोजित कन्या श्री योजना के तहत कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.

उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी जिलों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने साथ ही जांचें बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के नए वैरिएंट बी-4 और बी-6 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। कई राज्यों से तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई नया वैरिएंट नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर सभी जिलों को सैंपल जांच बढ़ाने के साथ कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. शैलजा भट्ट ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि संक्रमण का कोई नया वैरिएंट का मामला सामने नहीं आया है। सभी जिलों को कोविड संक्रमित व्यक्ति की नियमित निगरानी रखने के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा गया है। प्रदेश में वर्तमान में 316 सक्रिय मामले हैं।

अब सस्ता हो गया घर बनाना, सरिया और सीमेंट के दाम गिरे, यूपी एमपी को फायदा ज्यादा

संजय कुमार की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मकान बनाने में सबसे अधिक अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वह है सीमेंट और सरिया, अगर इन दोनों सामग्रियों के दाम अधिक हो जाएं, तो निश्चित ही घर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, ऐसा ही पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, सरिये व सीमेंट के दाम आसमान छूने के कारण लोगों को घर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था, लेकिन अब कुछ राज्यों में अचानक सरिये के दाम में करीब 32 हजार रुपए टन की गिरावट आ गई है, जिसका सीधा लाभ अब उपभोक्ताओं को मिलेगा, वहीं सीमेंट भी पहले की अपेक्षा सामान्य दरों पर मिलने लगी है।आपको बता दें, सरिये के दाम यूपी एमपी सहित कई राज्यों में लगभग 80 हजार रुपए टन यानी करीब 10 क्विंटल सरिया, इसके दाम 8 हजार 200 रुपए क्विंटल तक हो जाने के कारण लोगों को सरिया और सीमेंट खरीदना मुश्किल हो रहा था, कई लोगों ने तो अपने

घरों के निर्माण कार्य भी रोक दिए थे, क्योंकि इतना महंगा सरिया कौन मकान में लगवा सकता है। देश के कई राज्यों में अब दाम वर्तमान में 45 से 50 हजार रुपए टन हो गए हैं, यानी सरिये पर सीधा 32 हजार रुपए का फर्क आया है। इससे निश्चित ही घर बनाने वाले लोगों को काफी राहत महसूस होगी।इस साल फरवरी में सरिये के दाम 80 हजार रुपए टन पहुंच गए थे। जो वर्तमान में गिरकर 45000 से 50000 रुपए प्रति टन रह गया है, इस तरह से करीब 28 हजार रुपए टन की गिरावट सरिये में आई है।

20 से 60 रुपए कम हो गई सीमेंट

कई प्रदेशों में सीमेंट के दामों में भी इन दिनों गिरावट नजर आ रही है, पिछले चंद दिनों में ही सीमेंट के दामों में 20 से 60 रुपए प्रति बोरी के मान से गिरावट आई है। पहले जो सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी पहुंच गई थी, वहीं सीमेंट अब 380 रुपए प्रति बोरी मिलने लगी है, ऐसे में सीमेंट और सरिये के दामों में आई गिरावट का लाभ मिलने से लोगों को काफी राहत मिली है।

अपने बच्चे को बनाइये स्मार्ट और इंटेलिजेंट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्मार्ट बने। इसके लिए पेरेंट्स बहुत-सी कोशिशें करते हैं। कोई अपने बच्चों का ट्यूशन जल्दी लगवा देता है, तो किसी को कम उम्र में ही स्किल्स के लिए कोचिंग सेंटर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। पेरेंट चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी उनका बच्चा हर एक्टिविटी में तेज हो। आप भी अगर ऐसा ही चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें जरूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे स्मार्ट बन सकें।

बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए उन्हें जरूर सिखाएं ये चीजें

पेरेंट चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी उनका बच्चा हर एक्टिविटी में तेज हो। आप भी अगर ऐसा ही चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें जरूर फॉलो करनी चाहिए। इससे बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है। आइए, जानते हैं वे खास चीजे

हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी बच्चों को कोई और फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं। इससे बच्चे के पास एडिशनल स्किल भी आ जाएगी और आगे बच्चे के कॅरियर में एक स्कोप भी जुड़ जाएगा।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाएं

म्यूजिक सीखना समय की बर्बादी नहीं है। यह न सिर्फ एडिशनल स्किल है बल्कि इससे दिमाग शांत भी रहता है। साथ ही चीजों को देखने और महसूस करने की क्षमता भी बढ़ती है।

जल्दी उठने की आदतजल्दी उठने की आदत बचपन से सिखानी बहुत जरूरी है। इससे बच्चों का दिमाग एक्टिव रहता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं। ऐसे मेंबच्चों को जल्दी उठने की आदत सिखाएं।

मेडिटेशन : मेडिटेशन करने से बच्चे का दिमाग शांत रहता है और उसकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर बनती है। बच्चों को मेडिटेशन के फायदे भी बताएं। इससे बच्चा अच्छी तरह फोकस भी कर पाएगा।

कोटद्वार का चहुमुखी विकास मेरा लक्ष्य : ऋतू खडूड़ी , स्पीकर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण अपनी विधान सभा कोटद्वार के हर इलाके को विकास से जोड़ना चाहती हैं , यही वजह है कि दिल्ली से लखनऊ और देहरादून से कोटद्वार तक वो रोजाना अधिकारीयों से संपर्क कर योजनाएं बना रही हैं। इसी कड़ी में ज्यादातर समय विधान सभा कोटद्वार के लोगों के बीच नज़र आ रही हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुन कर समाधान कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास उनका संकल्प है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालपानी एवं मवाकोट पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का उत्साह पूर्वक जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों की जन समस्याओं को सुना एवं पूर्ण रुप से निस्तारण का आश्वासन दिया ।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। कहा कि हर जगह समान रूप से विकास कार्य होंगे और किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आयेगी। उन्होंने कहा की जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जनता की समस्याओं का निराकरण करना एवं विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है उन्होंने कहा है कि यह कार्य कोटद्वार विधानसभा में बखूबी होगा । क्षेत्र का कोई भी कोना विकास के उजाले से अछूता नहीं रहेगा। ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि वह लगातार प्रयासरत है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क, पेयजल, विद्युत सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए जिससे कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित हो।

इस अवसर पर मवाकोट में पार्षद दीपक लखेड़ा, राजेंद्र खेरवाल, बीना जोशी, जगमोहन राणा, शशिकांत जोशी, प्रमोद बहुखंडी, शांति थापा, अनूप नेगी एवं लाल पानी क्षेत्र में महानंद ध्यानी, पुष्पा देवी, भगवती देवी, रजनी देवी, उषा देवी, श्यामा देवी, रजनी नेगी, दीपक पांडे, पारस भट्ट, इंद्रजीत सिंह, कैलाश चंद, मदन चौहान, सुंदरी देवी, विजय रावत, यशवंत रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

मातृ मृत्यु अनुपात एवं शिशु मृत्यु अनुपात में कमी लाना प्राथमिकता : डॉक्टर सरोज नैथानी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात एवं शिशु मत्यु दर को कम करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शीर्ष प्राथमिकता है यह बात डॉक्टर सरोज नैथानी मिशन निदेशक एन एच एम द्वारा कही गई है । इस कार्यक्रम के लागू होने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच प्रसव संबंधी सेवाओं एवं प्रसव के उपरांत होने वाली जटिलताओं आदि को कम करने में सहायक सिद्ध होगा डॉ नैथानी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने गुणवत्ता देखभाल में सुधार लाने और गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने हेतु उच्च डिलीवरी लोड सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मिडवाइफ के नेतृत्व वाली देखभाल इकाइयों एम एल सी यू के माध्यम से परी क्लिप मिडवाइफ सेवाएं प्रदान की जानी है.डॉक्टर नैथानी ने बताया प्रदेश में मौजूदा नर्स मिडवाइफरी जो चयन प्रक्रिया को पूरा करती है उन्हें 18 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर कर मिडवाइफरी एन पी एम मे नर्स प्रैक्टिशनर के रूप में तैयार किया जाएगा। एन पी एम हाई केस लॉड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मैं मिडवाइफ के नेतृत्व वाली देखभाल इकाइयों के माध्यम से देखभाल प्रदान करने में शामिल होंगे ।मिडवाइफरी एजुकेटर्स मास्टर ट्रेनर्स का पुल है जिससे भारत में मिडवाइफरी प्रैक्टिस के लिए एन पी एम को प्रशिक्षित करने के लिए विकसित किया जाएगा। डॉ नैथानी ने बताया वर्तमान में राज्य से 6 मिडवाइफरी एजुकेटर का चयन किया गया है । जिन्हें 6 माह प्रशिक्षण नर्स मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान नर्सिंग कॉलेज मेरठ में प्रदान किया जा रहा है प्रशिक्षण उपरांत 6 चयनित मिडवाइफरी एजुकेटर को state मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में तैनात किया जायेगा।

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में फुटबॉल प्रीमियर लीग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून,1जुलाई । राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में फुटबॉल प्रीमियर लीग का सफल आयोजन 1 जुलाई डॉक्टर्स डे से शुभारंभ किया गया जिसमें प्रथम चरण में बॉयज टीम का मैच का समापन 1 जुलाई की संध्या को हुआ इस मौके पर डॉ प्रोफेसर आशुतोष सयाना, डॉ अशोक कुमार एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सुशील ओझा एसोसिएट प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग, डॉक्टर अनुपमा आर्य एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर अनिल जोशी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विभाग एवं डॉ अभय कुमार एसोसिएट प्रोफेसर शल्य चिकित्सा विभाग ने पहुंचकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉ आशुतोष सयाना ने कहा इस तरीके का खेल प्रतियोगिता छात्रों में अनुशासन एवं संघर्षशीलता का भाव लाता है अभी के समय में खेल प्रतियोगिताओं का महत्व और बढ़ जाता है जबकि छात्रों के बीच नशे एवं अन्य नकारात्मक गतिविधियों में ललिता बढ़ती जा रही है छात्रों में खेल भावना का विकास शिक्षा के साथ एक अनिवार्य घटक है कोविड-19 के बाद खेल प्रतियोगिताओं या खेल भावना से नकारात्मक विचारों को भी बचा जा सकता है

विभाग ढांचे की समीक्षा कर गैर ज़रूरी पदों को खत्म करें : मुख्य सचिव

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने विभागों द्वारा आयोग को भेजी जाने वाली रिक्तियों के अधियाचन के सम्बन्ध में सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रत्येक वर्ष भर्ती वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के अनुसार समय से अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें... उन्होंने विभागों को यह भी निर्देश दिए कि आयोगों को त्रुटिरहित अधियाचन भेजे जाएं...

मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि त्रुटिरहित अधियाचन भेजे जाने के लिए पोर्टल बेस्ड व्यवस्था बनाई जाए. पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने से त्रुटि होने की संभावना समाप्त हो जायेगी. साथ ही पोर्टल होने से समय की भी बचत होगी.मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपना कैलेंडर भी तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभागों के ढांचे भी बहुत पुरानी व्यवस्था पर चल रहे हैं.

विभागों में बहुत से ऐसे पद भी हैं जिनकी आधुनिक परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है और लंबे समय से रिक्त भी चल रहे हैं. जबकि जिन पदों की आवश्यकता है उन पदों का सृजन ही नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि प्रत्येक विभाग 2, 3 साल में अपने ढांचे की समीक्षा कर, आवश्यक पदों का सृजन करे और अनावश्यक पदों को समाप्त करे.मुख्य सचिव ने लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली डीपीसी बैठकों हेतु सचिवालय में कमरे की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए. संधू ने कहा कि इससे अधिकारियों का भी समय बचेगा. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा इस भर्ती वर्ष हेतु अधियाचन भेजे जाने हैं, और अभी तक नहीं भेजे हैं, अगले एक सप्ताह के भीतर अधियाचन आयोगों को भेज दें.

आज से लूज चेक और चेक बुक जारी करने पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

महविश की रिपोर्ट --
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आपके लिए ये खबर बेहद काम की है। न्यूज़ वायरस आपको बैंकों द्वारा चेक बुक जारी करने पर लिए जाने वाले शुल्क पर भी जीएसटी लगाने के फैसले की जानकारी दे रहा है. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में चेक पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है. यदि आप एक व्यवसायी हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो भुगतान के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में ज्यादातर चेक का उपयोग करते हैं तो आपका खर्च बढ़ सकता है क्योंकि चेक जारी की लागत 18 जुलाई से बढ़ जायेगी. जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में चेक पर 18 फीसदी कर को मंजूरी दे दी गई है.

यह कर चेक जारी करने या चेक बुक लेने पर लगेगा. बैठक चंडीगढ़ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. जुलाई से चेक और चेक बुक पर 18% जीएसटी लगेगा. वहीं मैप्स, वॉल मैप्स, हाइड्रोग्राफिक चार्ट और एटलस पर 12% जीएसटी लगेगाचेक पर जीएसटी का प्रभाव उन व्यवसायों पर प्रभाव पड़ सकता है जहां चेक अभी भी भुगतान का प्रमुख रूप है. खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और व्यवसायों में इसका प्रभाव पड़ेगा.

हालांकि, इस तरह के भुगतानों के लिए अब एक बड़ा हिस्सा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ईसीएस) जैसे ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन अब भी कई प्रकार के भुगतानों के लिए चेक एक पसंदीदा तरीका है.कई बैंक खाता खोलते समय शुरू में सीमित संख्या में चेक मुफ्त प्रदान करते हैं. जिसमें एक चेक बुक 10 या 25 लीफ होते थे. बाद में चेक बुक के लिए शुल्क लिया जाता है. बैंकों में इन सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से शुल्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. जिसमें चेक बुक जारी करना, ऑनलाइन और एसएमएस अलर्ट सेवाएं, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग शामिल हैं, जो उनके संचालन की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. छोटे और मध्यम व्यवसायों के मामले में जो एक महीने में अपने चालू खातों में सैकड़ों और हजारों चेक का उपयोग करते हैं पर इसका प्रभाव होगा.

प्रो0 डॉ आशुतोष सयाना ने दून मेडिकल कॉलेज वॉलीबॉल प्रीमियर लीग विजेता को सौंपी ट्रॉफी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का सफल आयोजन 25 जून से शुभारंभ किया गया था जिसमें द्वितीय चरण में बॉयज टीम के फाइनल मैच का समापन 30 जून को हुआ है। इस मौके पर डॉ प्रोफेसर आशुतोष सयाना, डॉ अशोक कुमार एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स ,डॉक्टर सुशील ओझा एसोसिएट प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग, डॉक्टर अनुपमा आर्य एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर अनिल जोशी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विभाग एवं डॉ अभय कुमार एसोसिएट प्रोफेसर शल्य चिकित्सा विभाग ने पहुंचकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथियों ने दोनों टीम के कप्तान आकाश पनाई एवं रोहन कांत को बधाई दी और कहा कि पठन-पाठन कार्य के साथ खेलों का आयोजन करने से शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है दिल की बीमारियों से भी बचे रहते हैं और याददाश्त भी मजबूत होती है। प्राचार्य प्रोफेसर डॉ आशुतोष सयाना ने विजय और उप विजेता टीम को टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया

बेमिसाल बेटियों ने किया कमाल - 12वीं में अव्वल आयी सिर से जुडी वीणा और वाणी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सिर के हिस्से से एक-दूसरे से जुड़ी जुड़वा बहनों ने 12वीं की परीक्षा में किया कमाल,CA बनने का है सपनाबलवान व्यक्ति को हिमालय डरा नहीं शकता , इस पंक्ति को सिर के हिस्से से एक-दूसरे से जुड़ी जुड़वा बहनों ने अर्थपूर्ण बनाया है। तमाम मतभेदों को पार कर हैदराबाद के मुखिया से जुड़ी दो बहनों ने एक मिसाल कायम की है. दोनों बहनों ने तेलंगाना इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मंगलवार को इंटर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए परिणाम घोषित किए। उम्मीदवारों में वीना और वाणी नाम की दो जुड़वां बहनें हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। इस अवसर पर तेलंगाना जनजातीय कार्य एवं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सतवती राठौर ने वाणी और वीना को विशेष बधाई दी। उन्होंने वीना और वाणी की मदद करने वाले अधिकारियों को भी बधाई दी।वाणी और वीना 12वीं बोर्ड के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। वाणी और वीना ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, "हमारी महत्वाकांक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने की है।" इसलिए 12वीं के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फाउंडेशन कोर्स में शामिल होंगे। वीना ने 10वीं की परीक्षा में 9.3 ग्रेड और भाषण में 9.2 ग्रेड हासिल किया है।

हर जाति के लिए खुला महामंडलेश्वर बनने का रास्ता, लेनी पड़ेगी डिग्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भारत में आस्था और धार्मिक संस्थानों की अपनी विशेष अहमियत है। भारत की पहचान आध्यत्मिक गुरु , संत समाज , मठ मंदिर और महाकुंभ मेले से जुड़े उसके पूरे 13 प्राचीन अखाड़ों का अद्भुत इतिहास सनातनी परंपरा का केंद्र है। लेकिन जिस तरह से संत समाज के अंदर से भी अक्सर विवादित बाबाओं का कारनामा उनकी विवादित जीवनशैली और आपराधिक प्रवृत्ति हिंदू आस्था और धार्मिक संस्थानों की बदनामी कराती रही है उसे रोकने के लिए अब अखाड़ा प्रबंधन सामने आया है। समय के साथ आधुनिकता के इस दौर में बदलाव के कई फार्मूले निर्धारित किए हैं। मतलब आप किसी भी जाति से हों अगर हिंदू धर्म को समझने और पढ़ने वाला बाबा बनना चाहते हैं और महामंडलेश्वर बनने की सोच रहे हैं तो उसे कई मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि अब बाबा बनना और महामंडलेश्वर बनना आसान नहीं होगा इसके लिए अनपढ़ और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री बैन हो जाएगी और हर जाति के योग्य लोगों का महामंडलेश्वर बनने का रास्ता खुल जायेगा। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाते हुए सनातन धर्म के प्रति आस्था और विद्वता के आधार पर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के दरवाजे हर जाति के संतों के लिए खुलेंगे। इसके साथ ही अब महामंडलेश्वर की पदवी पाना भी आसान नहीं होगा। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही भविष्य में महामंडलेश्वरों की ताजपोशी करेगा।

महामंडलेश्वर बनने के लिए आचार्य की डिग्री और मठ मंदिर की गद्दी होना अनिवार्य होगा। जात पात का भेदभाव दूर करने के लिए अखाड़ा सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी अपनाएगा।सनातन धर्म के प्रति आस्था और विद्वता के आधार पर अखाड़े के दरवाजे हर जाति के संतों के लिए खुलेंगे। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी सचिव एवं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि वक्त के साथ साधु-संन्यासियों की दीक्षा में भी बदलाव जरूरी है। महामंडलेश्वर की पदवी बेहद गरिमामयी है। अभी कई महामंडलेश्वर अनपढ़ हैं। सनातन धर्म के प्रति ज्ञान नहीं है। विवादित बयानबाजी करते हैं। पदवी लेने के बाद गृहस्थ जीवन में हैं।इन्हीं विसंगतियों को रोकने के लिए अखाड़ा स्तर पर महामंडलेश्वर की संन्यास दीक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता की जा रही है। कम से कम आचार्य की डिग्री जरूरी होगी। साथ ही मठ-मंदिर की गद्दी की अनिवार्यता होगी। इन मापदंडों पर खरा उतरने वाले संतों को ही महामंडलेश्वर की संन्यास दीक्षा दी जाएगी।

एक सप्ताह के भीतर कमेटी के सदस्यों के नाम होंगे सार्वजनिक

अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि के स्तर पर कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सदस्य ही महामंडलेश्वर की पदवी के लिए आवेदन करने वालों की शैक्षिक योग्यता जांचने के साथ सनातन धर्म के प्रति उनके ज्ञान की परीक्षा लेंगे। श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि योग्यता के आधार पर ही महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। इसके लिए जातपात का भेदभाव भी दूर किया जाएगा। हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान, शिक्षित और विद्वान संत को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। अखाड़ा स्तर पर गहन मंथन के बाद इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। आगामी एक सप्ताह के भीतर कमेटी के सदस्यों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

दीक्षा लेने वाले सैकड़ों, संपर्क में हैं सिर्फ 60

13 अखाड़ों में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी सबसे बड़ा अखाड़ा है। दोनों ही सन्यासी अखाड़े हैं। इनसे देश-विदेश के लाखों साधु-संतों जुड़े हैं। इन्हीं अखाड़ों में सर्वाधिक महामंडलेश्वर, श्री महंत, महंत और नागा संन्यासी हैं। श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से सैकड़ों संतों को संन्यास की दीक्षा के बाद महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है लेकिन अखाड़े के संपर्क में मात्र 60 महामंडलेश्वर हैं। बाकी महामंडलेश्वर दीक्षा लेने के बाद कभी अखाड़े में नहीं आए। कहां हैं अखाड़े को भी इसकी जानकारी नहीं है।अखाड़े से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद महामंडलेश्वर की पदवी आजीवन संत के नाम से जुड़ जाती है। संत अपने वाहनों के आगे महामंडलेश्वर सिद्धपीठ और मठाधीश जैसे बोर्ड लगाकर घूमते हैं। कई महामंडलेश्वर की मठ मंदिर की गद्दी नहीं है। संन्यास परंपरा के विपरीत गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होने से विवादित बयान देते हैं। इससे अखाड़े पर भी सवाल उठाए जाते हैं।

इन्हीं विसंगतियों को रोकने के लिए अखाड़ा शैक्षिक योग्यता और मठ मंदिर की अनिवार्यता का नियम बनाने जा रहा है।-श्रीमहंत रविंद्रपुरी, सचिव श्री निरंजनी अखाड़ासामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र में अखाड़ा सबसे आगेपंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। अखाड़े की ओर से मैनेजमेंट एवं फार्मेसी, डिग्री कॉलेज संचालित किया जा रहा है। यहां बच्चों को निजी कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट की तुलना में सस्ती शिक्षा मिलती है। अखाड़ा सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। बाढ़ सुरक्षा से लेकर आपदा, कोरोना काल में पीड़ितों के अलावा सरकार को आर्थिक मदद करता है।

'पांच साल में 'माननीयों' की रेल यात्रा पर 62 करोड़ खर्च', RTI में खुलासा

महविश की रिपोर्ट -
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

क्या आप जानते हैं हमारे वोट से जीतकर दिल्ली जाने वाले सांसद कितनी यात्राएं करते हैं ? हवाई और सड़क मार्ग की बात छोड़ दीजिये हम तो ट्रेन का हिसाब किताब बता रहे हैं। 2 साल कोरोना काल में जब देश भर में लम्बे समय तक ट्रेन सेवा भी प्रभावित रही है ऐसे हालात के बाद भी लोकसभा के मौजूदा और पूर्व सदस्यों को ट्रेनों में निशुल्क यात्रा की सुविधा से बीते पांच साल में सरकारी खजाने पर 62 करोड़ रुपए का भार पड़ा है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान 2020-21 में करीब 2.5 करोड़ रुपए इस तरह की यात्राओं पर खर्च हुए हैं। आपको यहाँ बता दें कि मौजूदा सांसद रेलवे की प्रथम श्रेणी की एअर कंडिशंड श्रेणी या एग्जिक्यूटिव श्रेणी की निशुल्क यात्रा की पात्रता रखते हैं।

मौजूदा सांसद रेलवे की प्रथम श्रेणी की एअर कंडिशंड श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी की निशुल्क यात्रा की पात्रता रखते हैं। उनके जीवनसाथी भी कुछ शर्तों के साथ मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। पूर्व सांसद भी अपने किसी साथी के साथ एसी-2 टियर में या अकेले एसी-1 टियर में निशुल्क यात्रा करने की पात्रता रखते हैं। मध्य प्रदेश के आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने इस बारे में जानकारी मांगी थी।इसके जवाब में लोकसभा सचिवालय ने बताया कि उसे 2017-18 और 2021-22 में वर्तमान सांसदों की यात्रा के बदले में रेलवे की ओर से 35.21 करोड़ रुपए का बिल मिला, वहीं पूर्व सांसदों की यात्रा के लिए 26.82 करोड़ रुपए का बिल मिला है।आरटीआइ जवाब में कहा गया कि सांसदों और पूर्व सांसदों ने महामारी के प्रकोप वाले वर्ष 2020-21 में रेलवे के पास का भी उपयोग किया, उनका बिल 1.29 करोड़ रुपए और 1.18 करोड़ रुपए था। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों समेत विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को दी जाने वाली कई छूट पर रोक लगा दी है, जिससे कुछ तबकों में नाराजगी है। वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सबसिडी खत्म करने के कदम की भी आलोचना हुई है।देश भर के ज्यादातर सांसद हवाई यात्रा भी करते हैं। इसके साथ साथ सड़क मार्ग से जो ट्रेवेल होता है वो अलग। ऐसे में अगर हिसाब लगाया जाए तो तीनों सुविधाओं को मिलकर एक बड़ी धनराशि माननीय सांसदों के मद में खर्च दिखाए जाने का अनुमान नज़र आता है।

जानिए झूठी FIR से बचने का कानूनी उपाय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आप और हम अक्सर सड़क पर चलते समय रोड एक्सीडेंट की घटना तो देखते ही रहते हैं। कहीं मामला तुरंत खत्म हो जाता है तो कहीं विवाद कोर्ट और पुलिस तक पहुँच जाता है और ज्यादातर मामलें में एफआईआर भी दर्ज़ हो जाती है। हो सकता है वो फ़र्ज़ी शिकायत हो या आप बेकुसूर हों और सामने वाले शख्स ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज़ करा दी है। अब ऐसे में आप झूठी एफआईआर से कैसे निपट कर बच सकते हैं ये सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। लिहाज़ा न्यूज़ वायरस आपको काम की बात बता रहा है ध्यान से पढियेगा। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा वाकया हो जाए तो जानते हैं क्या करना चाहिए? अगर हमारी गलती नहीं है और कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो इसका ये सॉल्यूशन है।

आप भी कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाना। इन सब से बचने के लिए बॉडी कैमरा या हेलमेट पर एक कैमरा लगाकर चल सकते हैं। जिससे आप रोड पर होने वाली घटनाओं की वजह से खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक्सीडेंट नहीं किया है और आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी जाए तो...आपके पास सिर्फ एक उपाय है। हाईकोर्ट से कथित FIR को रद्द कराना होगा। आप हाईकोर्ट में CrPC की धारा 482 के तहत केस से छुटकारा पाने के लिए FIR रद्द कराने की याचिका दायर कर सकते हैं।

झूठी FIR कराने वाले पर कर सकते हैं मानहानि का केसजब हाईकोर्ट में आपके पक्ष में जजमेंट आता है यानी आप बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तब आप चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ (जिसने आपके ऊपर झूठी FIR दर्ज की थी) मानहानि का केस कर सकते हैं। इसमें आप मुआवजा (CrPC 250) ले सकते हैं, या उसको सजा भी दिलवा सकते हैं।मानहानि का केस नहीं करना है तो IPC की धारा 211 का कर सकते हैं इस्तेमालIPC की धारा 211 के तहत आप उस व्यक्ति खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद उसे 2 साल की सजा और जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है।पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाईIPC की धारा 182 के तहत जिस भी पुलिस अधिकारी ने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

उसे इस सिचुएशन में 6 साल तक की सजा या एक हजार तक का जुर्माना हो सकता है। या दोनों भी हो सकता है।चलते-चलते ये भी जान लेते हैं...एक्सीडेंट होने पर लगती हैं IPC की यह धाराएंIPC की धारा 337- यह ऐसे मामले में लागू होती है जहां लापरवाही से गाड़ी चला कर किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाई गई हो। जैसे-कोई वाहन रोड पर कट मारता हुआ निकल रहा है या फिर दूसरे की गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है।ओवरटेक करने में दूसरे व्यक्ति की गाड़ी गिर जाती है। गिरने पर उसको साधारण चोट आती है।व्यक्ति को कोई खरोंच या फिर कहीं छोटा-मोटा घाव हो जाए इसे साधारण चोट माना जाता है।

ऐसी सिचुएशन में धारा 337 के तहत पुलिस एक्शन लेती है। जिसमें 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।IPC की धारा 338- यह ऐसे मामले में लागू होती है जहां लापरवाही से गाड़ी चला कर किसी व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा हो या फिर उसे गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। जैसे-किसी के हाथ-पैर टूट जाते हैंकिसी की उंगली टूट जाती है।कोई बड़ा गहरा घाव हो जाता है।ऐसी सिचुएशन में धारा 338 के तहत पुलिस एक्शन लेती है और आरोपी को 2 साल तक की जेल और जुर्माना लग सकता है। याद रखें- जब किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत नहीं होती है,लेकिन गंभीर चोट पहुंचती है। उस मामले में यह धारा लागू होती है।

आज से इन सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों पर लगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट - न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आज से आप अपनी आदत में सुधार ले आइये क्योंकि घर से बैग लेकर नहीं निकले तो सब्जी राशन लेने के लिए आपको सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नियां और बैग नहीं मिलेंगे। यही नहीं अगर आप प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट लेकर चलते हैं तो आपकी जेब भी ढीली हो सकती है। उत्तराखंड सहित आज से पुरे देश में केंद्र सरकार की ओर से प्लास्टिक से निकलने वाले कचरे के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए सामान जैसे ईयर बड स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक, कप गिलास, काटा चम्मच, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी सिगरेट पैकेट रैपर, पीवीसी बैनर और टेट्रा पैक के साथ मिलने वाली स्टिक पर बैन लग चुका है।मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, "पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा।"पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना: 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने के बाद अगर कोई भी आम आदमी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो फिर उस पर 500 से 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं अगर कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत उस पर कार्रवाही की जा जाएगी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माने या फिर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

डीएम राजेश कुमार की सख्ती का नमूना - 20 रूपये की ओवर रेंटिग पर 75 हजार का चालान

देहरादून के जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को अवस्थित शराब की दुकानों में 'यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी को प्राप्त हुई शिकायत पर शुक्रवार को आबकारी विभाग के टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गोपनीय तरीके से विदेशी मदिरा डांडालखौंड में शराब विक्रेता से बीयर एवं शराब की बोतल क्रय की गई। उक्त दुकान में बीयर की प्रति बोटल पर 20 रूपये अतिरिक्त ओवर रेटिंग करते हुए पाया गया, जिस पर टीम द्वारा 75 हजार रूपये का चालान किया गया है ।

देहरादून में मौजूद शराब की दुकानों के निरीक्षण के दौरान डांडालखौंड स्थित विदेशी शराब की दुकान में प्रति बीयर की बोटल पर एम.आर.पी. से 20 रूपये अतिरिक्त लिया जा रहा था। जिस पर कार्यवाही करते हुए 75 हजार का चालान किया गया। टीम द्वारा इस दुकान के अनुज्ञापी एवं विक्रता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। दुकान में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। दुकान में ''यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है'' का पोस्टर बैनर ठीक प्रकार से चस्पा होना चाहिए। तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

संपादकीय

जिम्मेदार बने मुस्लिम समुदाय

उदयपुर में जिस तरह की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना हुई है, वह बहुत चिंताजनक है. समाज में लोगों को संवेदनशीलता रखनी चाहिए और धर्मांध होकर जो लोग ऐसी वारदातें कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए. उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी सबक मिले, लेकिन हर घटना के बाद केवल निंदा कर और दोषियों को सजा देकर ही इतिश्री नहीं होनी चाहिए. आज पूरे देश और समुदाय के लिए यह सोचने का समय है कि बढ़ती धर्मांधता को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? अगर कोई कहे कि ऐसी घटनाएं प्रतिक्रियास्वरूप हो रही हैं, तो उससे पूछा जाना चाहिए कि बाकी देशों में फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह की बातों की आड़ लेने का समय निकल गया है. मुस्लिम समाज को समस्या को ठीक से समझने और अमल करने की जरूरत है, अन्यथा हालात और ज्यादा खराब होंगे. पूरे देश में माहौल मुस्लिम समाज के विरुद्ध होता जायेगा और इसके लिए समुदाय नहीं, बल्कि समुदाय के भीतर के कट्टरपंथी और दिशाहीन तत्व जिम्मेदार होंगे. इस कारण ऐसा हुआ, उस कारण वैसा हुआ जैसे बहाने निकालने की प्रवृत्ति उचित नहीं है. कोई ऐसी बातों को सुनना भी नहीं चाहता है. समुदाय के वैसे संगठनों को आत्मसमीक्षा करने की आवश्यकता है, जो कट्टर विचारों को बढ़ावा देने और ऐसी मानसिकता बनाने में योगदान देते हैं. ऐसी सोच व्यक्ति को बहुसांस्कृतिक समाज में रहने योग्य नहीं बनाती है और उसे अलग-थलग कर देती है. जो समझ या शिक्षण सामग्री कट्टरता को बढ़ाने में सहायक होती है, उसे भी हटाने का समय आ गया है. यह देखना होगा कि कोई शिक्षण सामग्री समाज में समरसता पैदा करती है, भाईचारा बढ़ाती है, सामाजिक विकास में योगदान देती है या फिर कहीं न कहीं वह लोगों को अलग-थलग करती है, इस्लाम को बदनाम करती है और विकास में भी बाधक बनती है. ऐसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध देश को भी खड़ा होना है, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम समाज को उन तत्वों के खिलाफ खड़ा होना होगा, जिनके विचार जाहिलाना और सोच कट्टरपंथी है. वे धर्म का जो असली व बुनियादी मर्म है, उसे समझने-समझाने की बजाय धार्मिक चिह्नों के प्रदर्शन को ही धर्म माने बैठे हैं. ऐसे तत्व आध्यात्मिकता के बजाय आडंबरवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं. आज भी अगर इस्लाम के मूल को नहीं समझा जायेगा, तो बहुत देर हो जायेगी. आप इंसानियत की खिदमत कीजिये, ईश्वर में आस्था रखिये और समाज की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करिये, यह धर्म है. इन चीजों को छोड़ कर आडंबर की ओर रुझान होना चिंताजनक है.

दून में 4 जुलाई से शुरू होगा समाज कल्याण विभाग का बहुउद्देशीय शिविर : डॉ0 आर राजेश कुमार, जिलाधिकारी

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने बताया है कि जनपद के दूर-दराज के पात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद देहरादून में समस्त विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक विकासखण्डवार/क्षेत्रवार शिविर का आयोजन विकासखण्ड रायपुर में 4 जुलाई को जूनियर हाईस्कूल मालदेवता, 5 जुलाई को शेरा ग्राम पंचायत भवन रायपुर, 6 जुलाई को रामनगर डांडा पंचायत भवन रायपुर, विकासखण्ड विकासनगर में 13 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत एटनबाग (मिनी स्टेडियम) विकासनगर, 15 जुलाई को ग्राम पंचायत जीवनगढ़ (शर्मा फार्म हाउस), विकासखण्ड चकराता में 22 जुलाई को विकासखण्ड मुख्यालय चकराता तथा 9 सितंबर को पीडब्लूडी गेस्ट हाउस क्वांसी चकराता , विकासखण्ड कालसी में 29 जुलाई को विकासखण्ड मुख्यालय कालसी तथा 12 अगस्त को सब्जी मंडी समिति कार्यालय सहिया, विकासखण्ड सहसपुर में 3 अगस्त को बहुउद्देशीय भवन सुद्धोवाला, देहरादून क्षेत्र में 8 अगस्त को सयुंक्त चिकित्सालय प्रेमनगर में, विकासखण्ड डोईवाला में 17 अगस्त को पंचायत घर भोगपुर तथा 24 अगस्त को पंचायत घर दूधली डोईवाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित अभिलेखों एवं योजनाओं के विवरण सहित बहुउद्देशीय शिविर में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में स्थानीय विधायकों एवं जन-प्रतिनिधियों/क्षेत्रीय महानुभावों को शिविर में आमंत्रित करने तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिविरों में दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु चिकित्सकों की टीम गठित करने तथा समस्त तहसीलदारों को शिविर में आने वाले आवेदकों के आय, जाति, स्थाई, निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

सामुदायिक, स्मार्ट पुलिसिंग में उत्तराखण्ड पुलिस को मिली BPR & D में सराहना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उस दिशा में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों की पुलिस और अन्य पुलिस संगठनों के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों पर एक किताब "स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्यप्रणालियां (Best Practices on Smart Policing)" प्रकाशित किया है। इसमें देश भर के पुलिस संगठनों के पुलिसिंग विषयक उल्लेखनीय कार्यों के कुल तीस चुनिंदा कार्यों को शामिल किया गया है।उपरोक्त संस्करण में उत्तराखण्ड पुलिस की बाल भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास हेतु चलाए गए ₹ऑपरेशन मुक्ति₹, स्मार्ट पुलिसिंग हेतु स्मार्ट चीता पुलिस की तैनाती और महिलाओं की थानों में पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिए समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की मुहीम पर विस्तृत आलेख प्रकाशित हुआ है।आपको बता दें कि कि ''ऑपरेशन मुक्ति'' अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ Integrated Drive चलाकर प्रभावी Enforcement के माध्यम से बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करना, भिक्षा न दिये जाने के सम्बन्ध में जनता को जागरूक करना, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित करना व उनके पुनर्वास हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना है। अभियान की थीम ''भिक्षा नहीं, शिक्षा दें''व ₹Educate a child₹ है। अभियान के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति से हटाकर कुल 1430 बच्चों का स्कूल/डेकेयर होम में दाखिला कराया गया है। चीता पुलिस को स्मार्ट बनाये जाने, उनकी कार्य क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाये जाने के लिए कुल 148 (30 महिला व 118 पुरूष) कर्मियों को एक माह का प्रशिक्षण देकर उनकी वर्दी में अतिरिक्त उपकरण जैसे- बॉडी ऑन कैमरा, मल्टीपल बैल्ट, शॉर्ट रेन्ज आर्म्स देकर 24 फरवरी 2021 को जनपद देहरादून में तैनात किया गया। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किये गये हैं। महिला सम्बन्धी एवं अन्य प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हेतु इन डेस्क की स्थापना की गयी है। पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अशोक कुमार ने इस उपलब्धी के लिए समस्त पुलिसजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की SMART (S-Sensitive & Strict, M-Modern with Mobility, A-Alert & Accountable, R- Reliable & Responsive, T-Trained & Techno-Savvy) Policing (स्मार्ट पुलिसिंग) की अवधारणा पर उत्तराखण्ड पुलिस अग्रसर है। उत्तराखण्ड पुलिस ने अपने व्यवसायिक कर्त्वय के साथ ही अपने मानवीय एवं नैतिक कर्त्वयों का भी निर्वहन कर पुलिस की छवि को बहुत निखारा है। हमारा उद्देश्य हमेशा ही पीड़ित केनद्रित एवं जन केंद्रित पुलिसिंग है। हमें इस छवि को बनाये रखना है।

थम गया रिवर राफ्टिंग का रोमांच, अब 2 महीने कीजिये इंतज़ार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमांचल और यूपी से देहरादून ऋषिकेश आने वाले सैलानियों को फिलहाल रिवर राफ्टिंग का मज़ा नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में मॉनसून की आमद के साथ ही ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध व्हाइट रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है. गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राफ्टिंग एक्टिविटी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक बंद रहेगी. अब 2 महीनों के बाद ही राफ्टिंग के शौकीनों को एक बार फिर इस स्पोर्ट का मौका मिलेगा. इधर, इस राफ्टिंग संचालन बंद होने से करीब 25 हज़ार परिवारों की आजीविका प्रभावित होने की बात कहकर स्थानीय व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस व्यवसाय को प्रोत्साहन दे.

ऋषिकेश में गंगा नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है, जिसके चलते इस एडवेंचर खेल के दीवानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. आलम यह है कि 2022 के इस सीजन में 5 लाख से ज्यादा सैलानी ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ उठा चुके हैं. राफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भट्ट का कहना है कि लोगों ने इस व्यवसाय को बखूबी खड़ा किया है और अब सरकार को चाहिए कि इन लोगों को सहारा दे.

राफ्टिंग को लेकर बढ़ रहे धंधे से स्थानीय व्यवसायी खुश हैं तो भट्ट बताते हैं कि यहां 25 हज़ार से ज़्यादा परिवार इस व्यवसाय से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं. भट्ट के मुताबिक करीब 254 कंपनियां यहां राफ्टिंग का संचालन कर रही हैं. अगर आप भी रिवर राफ्टिंग के शौकीन है और इस सीज़न में लुत्फ अभी तक नहीं उठा सके हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए. गंगा का जलस्तर कम होते ही सितंबर में एक बार फिर राफ्टिंग शुरू हो जाएगी.

ग्रामीण निर्माण विभाग में 15 करोड़ की लिमिट खत्म कर धनराशि की सीमा होगी असीमित : सतपाल महाराज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

- ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर अभियान्त्रिकी विभागों की कार्यदायी संस्था बनाया जायेगा
- ग्रामीण निर्माण विभाग की स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित

ग्रामीण निर्माण विभाग का स्वरूप अन्य सभी अभियान्त्रिक विभागों की भाँति होने के कारण निर्माण कार्य किये जाने की सीमा 15 करोड़ से बढाकर असिमित किये जाने पर मंथन चल रहा है। चूंकि वर्तमान में विभाग द्वारा अन्य गैर अभियान्त्रिकी विभागों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं इसलिए गैर अभियान्त्रिकी विभागों की कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को बनाये जाने हेतु भी विचार किया जा रहा है। ये जानकारी प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने ग्रामीण निर्माण विभाग की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह में दी है। ग्रामीण निर्माण विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में विभागीय लोगो का अनावरण करने के पश्चात विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, अभियंताओं और उपस्थित लोगों को स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं देते हुए ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण निर्माण विभाग पूरे प्रदेश में उच्च गुणवत्ता युक्त विभिन्न विभागों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्य भी कर रहा है। ग्रामीण निर्माण मंत्री ने बताया कि नाबार्ड पोषित एवं राज्य योजना के अन्तर्गत कुल 201 ग्रामीण मोटर मार्गों (लम्बाई 386.663 कि.मी.) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें 314 ग्रामों की कुल 1,54,993 जनसंख्या लाभान्वित हुई है। प्रदेश में कार्यरत तकनीकी विभागों, कार्यदायी संस्थाओं में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों हेतु स्थापना व्यय (वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.55 प्रतिशत) न्यूनतम है।ग्रामीण निर्माण मंत्री महाराज ने विभाग में तकनीकी संवर्ग के 487 पदों के सापेक्ष 238 लगभग (48 प्रतिशत) तथा गैर तकनीकी संवर्ग के कुल 398 पद के सापेक्ष 128 (32 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने के निर्देश देते हुए कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के बाद विभाग की कार्यक्षमता को तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। निर्माण के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास तथा शासन की कार्यप्रणाली में सूचना प्रोद्योगिकी के आधुनिक प्रयोगों को देखते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही जिससे सभी कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए विभाग को जिला योजना का सदस्य नामित किए जाने पर भी विचार चल रहा है।मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विभाग का स्वरूप अन्य सभी अभियान्त्रिक विभागों की भाँति होने के कारण निर्माण कार्य किये जाने की सीमा रू 15 करोड़ को असिमित किये जाने पर भी मंथन चल रहा है। विभाग द्वारा अन्य गैर अभियान्त्रिकी विभागों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। गैर अभियान्त्रिकी विभागों की कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को बनाये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।स्वर्ण जयंती समारोह में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, ग्रामीण निर्माण विभाग के सचिव नितेश झा, मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष अजय कुमार पंत, मुख्य अभियंता (कुमाऊं) नवीन चंद्रा, पूर्व मुख्य अभियंता बी.एस. कैडा, पूर्व मुख्य अभियंता वाई. डी. पांडे, सहित नगर निगम क्षेत्र रायपुर के अनेक पार्षद एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

हरदा की धनदा को चेतावनी, यूरिया दे पाने में कॉपरेटिव विभाग लाचार : हरीश रावत

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट - न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने पहले 100 दिन की उपलब्धियों को अलग अलग कार्यक्रमों में जहाँ जनता को बता रही है वहीँ विपक्ष के सबसे बुजुर्ग लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भला ऐसे में कैसे खामोश रहते। लिहाज़ा उन्होंने एक बार फिर शब्दबाण छोड़े हैं।

अक्सर मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि 100 दिनों के समय को सरकार के आंकलन के लिए कम है लेकिन इशारों में उन्होंने धामी कैबिनेट के मंत्रियों की खिंचाई ज़रूर कर दी. यही नहीं, रावत ने तीन दिन बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर मोर्चा खोलने की चेतावनी भी दे डाली है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह कॉपरेटिव विभाग संभालने वाले मंत्री धनसिंह रावत के घर के बाहर उपवास पर बैठेंगे. सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए रावत ने लिखा कि उत्तराखंड के हिस्से के यूरिया की स्मगलिंग की जा रही है और किसानों को खाद, यूरिया दे पाने में कॉपरेटिव विभाग लाचार हो गया है. 'हालात ऐसे बन गए हैं कि मैं मंत्री जी के घर के बाहर उपवास पर बैठने को मजबूर हो रहा हूं.' हालांकि रावत ने दो से तीन दिनों का समय धनसिंह रावत को ज़रूर दिया है... देखना दिलचस्प होगा कि क्या हरदा के धरने से पहले धनदा कोई बयान देते है या लोग एक बार फिर हरीश रावत की धरना पॉलिटिक्स का नज़ारा देखेंगे।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा